मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2797
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अपशिष्ट एवं सीवेज जल शोधन प्रबंधन संयंत्रों का लगाया जाना

2797. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः
श्री सौमित्र खानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में कचरा, अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अपशिष्ट और सीवेज जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से सीवान संसदीय क्षेत्र के शहरों के लिए वर्ष-वार और शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने का कार्य किया है/करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): कचरा, अपशिष्ट और सीवेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सरकार ने दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) तथा दिनांक 25 जून, 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) प्रारंभ किया है।

चरण-I में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 तक प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी शहरों में सुरक्षित स्वच्छता और नगरपालिका के ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना है।

अमृत 2.0 को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल संरक्षित' बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। अमृत 2.0 देश के 500 शहरों से लेकर सभी सांविधिक कस्बों तक जलापूर्ति में सार्वभौमिक कवरेज को बढ़ाकर जीवन को आसान बनाएगा।

(ग) और (घ) : एसबीएम-यू के तहत केंद्रीय (सीएस) हिस्से की सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के एमएसडब्ल्यू प्रबंधन संयंत्रों की संस्थापना के लिए दी जाती है, जैसे अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी), अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई), जैव-मीथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) और पुराने अपशिष्ट डंपसाइट शोधन आदि एसडब्ल्यूएम घटक के तहत एसबीएम-यू (दिनांक 02.10.2014 से 30.09.2021 तक) में 7,365.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और एसबीएम-यू 2.0 (दिनांक 01.10.2021 से 01.10.2026 तक) में 10,930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत केंद्रीय निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं, न कि शहरों को। इसलिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निधियों का शहरवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत बिहार राज्य को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	एसबीएम चरण	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
1	एसबीएम-यू (वर्ष 2014 से 2021)	556.68	385.95
2	एसबीएम-यू 2.0 (वर्ष 2021 से 2026)	1204.80	209.47

बिहार में यूएलबी-वार ठोस अपशिष्ट संयंत्रों का विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है

अमृत के तहत, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत, 34,488 करोड़ रुपये की लागत वाली 888 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 32,022 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से निष्पादित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में

अब तक 68,198 करोड़ रुपये की लागत वाली 595 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अमृत के तहत, बिहार के सीवान निर्वाचन क्षेत्र में 104.92 करोड़ रुपये की लागत की 02 जलापूर्ति परियोजना तथा 0.63 करोड़ रुपये की लागत की 01 पार्क एवं हरित क्षेत्र परियोजना शुरू की गई थी और पूर्ण की जा चुकी हैं।

अमृत 2.0 के तहत, बिहार के सिवान निर्वाचन क्षेत्र के लिए 105.24 करोड़ रुपये की लागत की 01 जलापूर्ति परियोजना और 372.59 करोड़ रुपये की लागत की 01 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

(ङ): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की निगरानी एसबीएम-यू की प्रगति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा तथा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरों में एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में स्वच्छता की स्थिति तथा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाता है।

*****